Supplementary Demands for Grants (2025- 26)- First Batch for 2025-2026 under consideration

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, अब सभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच - 2025-26 को चर्चा व मतदान के लिए लिया जाएगा।

अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर कई कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं। जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्ची भेज दें, जिसमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्या लिखी हो, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात् नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि माननीय सदस्य उस सूची में कोई विसंगति पाते हैं तो वे कृपया इसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दे दें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15 से 21, 23 से 30, 32, 35 से 38, 43 से 55, 58 से 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76 से 79, 82, 85 से 89, 94 से 99 और 101 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।?

माननीय सभापति : श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : सभापति महोदया, इससे पहले कि मैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स के विषय पर अपनी कुछ बात रखूं, उसके पहले अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत पर कुछ कहना चाहूंगा। मैं वित्त मंत्री जी से यह कहकर शुरू

करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े असत्य हैं और दावा किताबी है। सरकार बड़े जोर-शोर से कह रही है कि पिछले क्वार्टर में इतनी ग्रोथ हुई, इत्यादि। जो ग्रोथ का आंकड़ा दिया गया है, जो विकास दर दी गई है, वह कितनी विश्वसनीय है? सबसे पहले तो इसी पर प्रश्न उठ रहे हैं और ये प्रश्न केवल हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में उठ रहे हैं। आईएमएफ ने मात्र 15 दिन पहले ही सरकार की अकाउंटिंग को ?सी? ग्रेड देने का कार्य किया। यानी कि आईएमएफ प्रश्नचिन्ह उठा रहा है कि सरकार कैसे अकाउंटिंग करके यह विकास दर देश के सामने रख रही है? आईएमएफ ही नहीं, देश के बहुत से अर्थशास्त्रियों ने कई बार इसे पॉइंट आउट किया। जो नई सीरीज एनएसओ आई है, यह इनकम ग्रोथ के आधार पर विकास दर देश के सामने रखती है, जबकि एक्सपेंडीचर ग्रोथ के आधार पर होना चाहिए। अगर यूएस कनवेंशन देखें, अमेरिकी इकोनॉमी और बाकी कई अर्थव्यवस्थाओं में एक्सपेंडीचर ग्रोथ के हिसाब से होता है।

अगर इस क्वार्टर में भी एक्सपेंडिचर ग्रोथ के हिसाब से अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट देखें तो 6.1 प्रतिशत होना चाहिए। आपने बहरहाल दूसरे तरीके से कैलकुलेट किया है। अगर हम आपकी बात मानें, आपके दिए आंकड़ें मानें और नई सीरिज़ के आंकड़े मानें तो भी इस विकास दर पर प्रश्न चिह्न लगता है क्योंकि यूपीए के दस वर्षों में औसतन अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.1 प्रतिशत थी। आपके द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 11 वर्षों में औसत दर 5.75 प्रतिशत तक पहुंची है। क्या यह हर्षोल्लास की बात है?

महोदया, सरकार कह रही है हमारी विकास दर रिकॉर्ड हुई है। विकास दर रिकॉर्ड नहीं हुई है, रिकॉर्ड कुछ और बने हैं और 78 सालों के रिकॉर्ड लुढ़के हैं। मैं 78 साल यानी आठ दशको के आठ रिकॉर्ड बताना चाहता हूं जो आपकी अर्थव्यवस्था की मौजूदा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे। 78 वर्षों में अगर हमारी मुद्रा या करेंसी सबसे निम्नतर स्तर पर पहुंची है तो वित्त मंत्री जी आपके इस कार्यकाल में पहुंची है। मैं देख रहा था, आपका बयान आया कि रुपया इतना नहीं गिरा जितना डॉलर मजबूत हो गया। हम हरियाणा से आते हैं, कुश्ती खेलते हैं, यह तो वही बात हो गई कि दो पहलवान आपस में लड़े और जो हारा उसके पिता ने कहा कि मेरा बेटा नहीं हारा, दूसरा ज्यादा मजबूत था इसलिए हारा है। डॉलर मजबूत हुआ है, मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि एशिया की बाकी करेंसियों, इंडोनेशिया का रुपया, फिलीपींस का पीसो आदि की तुलना में आपके समय में रुपया वर्स्ट परफार्मिंग करेंसी साबित हुआ है। आपका पहला रिकॉर्ड यह बना है।

महोदया, आपको करंट एकाउंट डेफिसिट यानी व्यापार का घाटा की दूसरे रिकॉर्ड की बधाई हो। कितना निर्यात है और कितना आयात है, इसमें अगर 78 सालों में एक महीने का सबसे ज्यादा करंट एकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है तो वह इस साल के अक्टूबर में 41.7 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। आपने 78 सालों में दूसरा रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। यही नहीं, आज 1.3 प्रतिशत जीडीपी का करंट एकाउंट डेफिसिट है, जो कि अनुमानित अगले वर्ष बढ़कर 1.7 प्रतिशत होने जा रहा है।

महोदया, आपने 78 सालों में तीसरा रिकॉर्ड इनइक्वेलिटी यानी गरीब और अमीर के बीच के अंतर का बनाया है। कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस देश के एक प्रतिशत सबसे अमीर नागरिकों के हाथ में देश की 40 प्रतिशत सम्पत्ति और 65 प्रतिशत आय है। यह गरीब और अमीर में असमानता का 78 सालों का ही नहीं, बल्कि 100 साल का रिकॉर्ड है। वर्ष 1922 से अर्थशास्त्री इन आंकड़ों पर ध्यान दे रहे हैं। आपने 100 साल का अमीर और गरीब के बीच अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया है।

महोदया, पंकज चौधरी जी, एमओएस यहां उपस्थित हैं, उनके द्वारा राज्य सभा में उत्तर दिया गया है। हम उनको बधाई देते हैं कि आपकी पार्टी में उनकी पदोन्नति होने जा रही है। उन्होंने राज्य सभा में उत्तर दिया कि पिछले दस सालों में 16 लाख करोड़ रुपये राइट ऑफ हो गए। किसका राइट ऑफ हुआ? कॉरपोरेट का राइट ऑफ हुआ या किसान का हुआ? यह सब जानते हैं। यूपीए के समय हमने 78 हजार करोड़ रुपये किसान की एक साथ कर्ज माफी की थी। आपके समय में पिछले दस सालों 16 लाख करोड़ रुपये राइट ऑफ हुए, 78 सालों में यह चौथा रिकॉर्ड बना।

महोदया, अब पांचवें रिकॉर्ड की बात आती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इतनी मोनोपोली और डुओपोली प्राइवेट सैक्टर को कभी नहीं मिली, जितनी आपकी सरकार के समय में मिली है। आज हम क्या देख रहे हैं? आपने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का सपना दिखाया। हमारी सरकार के समय में एविएशन सैक्टर में जेट, किंगफिशर, स्पाइसजेट, एयर एशिया, विस्तारा, गो एयर में कम्पीटिशन था। लेकिन अब क्या है? 65 प्रतिशत मार्केट शेयर अकेले इंडिगो का है और 26 प्रतिशत एयर इंडिया का है, इस तरह से दोनों के मिलाकर 91 परसेंट मार्केट शेयर हो गए। अगर दोनों आपस में बात करके रेट तय कर लें तो हमारे देश के हवाई यात्रियों के पास कहीं पेटिशन का मौका नहीं होगा। इसी को डुओपोली और मोनोपोली कहते हैं। यह केवल एक सैक्टर तक सीमित नहीं है। टेलीकॉम सैक्टर में हमारी सरकार के समय में डोकोमो, युनिनॉर, एयरसेल, आइडिया, वोडाफोन, आइडिया, जीओ और एयरटेल थे, लेकिन अब सब समाप्त हो गया, केवल दो कंपनियां रह गई हैं, जिओ और एयरटेल। अगर दोनों का मिलाकर मार्केट शेयर देखें तो टेलीकॉम का 80 प्रतिशत मार्केट शेयर केवल जिओ और एयरटेल के पास है। अगर ये दोनों आपस में तय कर लें तो कन्ज्यूमर के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है।

वित्त मंत्री जी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि जो बड़ी-बड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं, जैसे अमेरिका में हर सेक्टर में डुओपॉली और मोनोपॉली को रोकने के लिए कंज्यूमर के हक में कानून है कि 30 प्रतिशत से ज्यादा किसी सेक्टर में किसी एक कंपनी का मार्केट शेयर नहीं हो सकता है। वहाँ एयरलाइंस और टेलीकॉम आदि सारे सेक्टर्स में तीस प्रतिशत मैक्सिमम शेयर है। यदि इससे ज्यादा होता है, तो वे उसे रोकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं, जहाँ तीस प्रतिशत से ज्यादा एक ही कंपनी का शेयर है। कार्गो में 30 प्रतिशत से ज्यादा अडानी का, कंटेनर में 50 प्रतिशत से ज्यादा अडानी का, एयरपोर्ट में 30 प्रतिशत से ज्यादा अडानी का, सिविल एविएशन और टेलीकॉम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही मीडिया में, मैं समझता हूँ कि रिलायंस और अडानी, सारी

मीडिया उनके ही पास है। मोनोपॉलीज़ और डुओपॉलीज़ का भी रिकार्ड बना है। देश के 78 साल में ऐसी कंपनियों के हाथ में अलग-अलग सेक्टर्स कभी नहीं गए।

छठा रिकॉर्ड अनइंप्लॉयमेंट पैटर्न का है। अनइंप्लॉयमेंट पैटर्न पिछले कई दशकों से एक संदर्भ में एक ही दिशा में जा रहा था। वह संदर्भ था कि लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जा रहे थे और कृषि क्षेत्र से आ रहे थे। एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमारी वर्कफोर्स की संख्या घट रही थी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ रही थी। आपकी सरकार में पिछले तीन वर्षों में यह ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर पिछले तीन वर्षों में देखें, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहाँ वर्ष 2014 में यूपीए के टर्म में 12.8 प्रतिशत लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे, आज वे घटकर 11.5 प्रतिशत ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रह गए हैं। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2014 में 42 प्रतिशत लोग थे, जो कि आज बढ़कर 46 प्रतिशत हो गए हैं। यानी कि यह ट्रेंड बदल गया और लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से वापस कृषि क्षेत्र में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह हमारे देश के लिए बहुत चिंताजनक ट्रेंड है, जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 78 वर्षों में आपने जो रिकॉर्ड बनाए हैं, उनमें से मैंने छः रिकॉर्ड बताए।

सातवाँ रिकॉर्ड डैट के बारे में है। आज तक कभी भी देश की सरकार और प्रदेश की सरकारें सभी को मिलाकर इतना कर्ज नहीं चढ़ा। गाँव-देहात में एक कहावत होती है कि कर्ज लो और घी पियो, बाद की चिंता किसको करनी है, जब ऊपर पहुँच जाएँगे। जो कर्ज लेकर घी पीते हैं, उनका क्या हाल होता है, सब अर्थव्यवस्थाओं का पता है। आपके समय इतना डैट हो गया है। आज मौजूदा स्थिति यह है कि स्टेट्स और सेंटर को मिलाकर हमारे देश में टोटल डैट जीडीपी का 82 प्रतिशत है। जितनी भी हमारी समकक्षीय अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं या पर कैपिटा इनकम के हिसाब से समकक्षीय हैं, जैसे- फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि किसी में भी 30-40 प्रतिशत से ज्यादा डैट नहीं है। अगर अमेरिका, जापान आदि की बात करें, तो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में इतना डैट होता है, क्योंकि वे इकोनॉमीज़ एक स्तर तक पहुँच जाती हैं। ये जो डैट है, आप रीसेंटली किस बात के लिए डैट ले रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए डैट ले रहे हैं। आप कर्ज ले रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए कर्ज ले रहे हैं। बिहार में आपने क्या किया?

मैं हरियाणा के बारे में बताना चाहता हूँ। वर्ष 2024 के चुनाव से एक साल पहले हरियाणा में कुल मिलाकर 8.6 लाख बीपीएल कार्ड थे। चुनाव के लिए आपने बीपीएल कार्ड्स की संख्या बढ़ाकर 52 लाख कर दी। हरियाणा के 2 करोड़ 53 लाख मतदाताओं में से 2 करोड़ लोग बीपीएल बन गए। चुनाव के समय हरियाणा की 75 प्रतिशत आबादी आपने बिलो द पॉवर्टी लाइन डिक्लेयर कर दी। चार-पाँच महीनों तक उन्हें राशन दिया, बीपीएल की सारी सुविधाएँ दीं और चुनाव के एक साल बाद आपने इनमें से आधे राशन कार्ड काट दिए। न तो इतनी तेजी से हरियाणा में गरीबी आई और न ही उसी रफ्तार से अमीरी आई। चाहे हरियाणा का उदाहरण हो या बिहार में 10 हजार रुपये देने की बात हो, आप कर्ज लेते जा रहे हैं। आपने देश के कर्ज का रिकॉर्ड बना दिया।

आठवाँ रिकॉर्ड प्रदूषण के बारे में है। देश के इतिहास में कभी इतना प्रदूषण नहीं हुआ, जितना कि वित्त मंत्री जी आपकी सरकार में हुआ। मैंने केवल आठ ही रिकॉर्ड बताए हैं, क्योंकि देश की आजादी के बाद आठ दशक ही हुए हैं, लेकिन आपने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। कुल मिलाकर आज अर्थव्यवस्था में बहुत फॉल्टलाइन्स हैं। आपकी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन जितना मजबूत होना चाहिए, वह उतना नहीं है।

सरकार पब्लिक स्पेंडिंग के हिसाब से अर्थव्यवस्था को ग्रोथ रेट की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पब्लिक स्पेंडिंग के लिए आप कर्ज ले रहे हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था का एक नया मॉडल हो गया है।

आप आउटकम्स और ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स को चुन रहे हैं। आप नारे दे रहे हैं- ?स्टार्ट अप इंडिया।? लेकिन स्टार्ट अप इंडिया की यह हक़ीकत है कि इस वर्ष स्टार्ट अप्स समाप्त हो गये हैं। इस तरह से, ?स्टार्ट अप इंडिया? नहीं, बल्कि शट डाउन इंडिया हो गया है। आप नारा दे रहे हैं- ?मेक इन इंडिया।? लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट घट रही है। आप कोरिया, वियतनाम, चाइना में जाकर पूछिए, जहाँ से प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में आ रहे हैं। अभी ?मेड फॉर इंडिया? का नारा चल रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति उसी तरह की है। आपने नोटबंदी के समय जो किया उसके बाद से हक़ीकत यह है, मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि कोई नौसिखिया मैकेनिक या मिस्त्री अगर कोई मोटर खोल दे, तो उसके बाद उसे उसको बांधना न आए। आज अर्थव्यवस्था की वैसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। इस तरह से, देश की अर्थव्यवस्था अनर्थ व्यवस्था की तरफ बढ़ गई है। वित्त मंत्री जी, यह हमारा मानना है।

अब मैं डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के कुछ सेक्टर्स की तरफ आता हूँ। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में भी जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, वैसे हम देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट में एक और कमी आई है, क्रिटिकल सेक्टर्स में कोई ग्रोथ रेट नहीं है। माइनिंग में कोई ग्रोथ रेट नहीं दिखाई दे रही है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई ग्रोथ रेट नहीं दिखाई दे रही है। मगर आपकी सरकार में जो क्रिटिकल विभाग हैं, उनमें आपकी सरकार की जो सिफारिश है, आप उसी को नहीं मान रहे हैं।

हेल्थ सेक्टर में, नैशनल हेल्थ पॉलिसी की एक सिफारिश है कि जीडीपी का ढ़ाई प्रतिशत हेल्थ सेक्टर को दिया जाए। आपने हेल्थ के लिए 1.4 प्रतिशत बजट में रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में, नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कहा गया है कि जीडीपी का मिनिमम 6 प्रतिशत एजुकेशन सेक्टर को दिया जाए, लेकिन आप इसमें 4.5 प्रतिशत पर ही संतुष्ट हैं। आर एंड डी के क्षेत्र में, किसी भी देश को आगे ले जाने का जो स्वप्न होता है, नैशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी में आपकी सरकार कह रही है कि बाकी देशों को देखते हुए, इसमें जीडीपी का मिनिमम 2 प्रतिशत खर्च किया जाए। लेकिन इसमें भी आप 0.6 प्रतिशत से ही संतुष्ट हैं।

डिफेंस सेक्टर में, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस यह रिपोर्ट दे रही है कि जीडीपी का मिनिमम 3 प्रतिशत डिफेंस को दिया जाए। मगर आपकी सरकार डिफेंस के लिए जीडीपी का 1.9 प्रतिशत बजट दे रही है। मैं डिफेंस सेक्टर के बारे में थोड़ा और खोलकर कहना चाहूंगा क्योंकि हमने अभी ?ऑपरेशन सिन्दूर? देखा। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान और

चीन ने एक होकर हमारे देश के खिलाफ काम किया। लेकिन हमारे देश की फौजों ने पराक्रम से उनकी चुनौतियों का सामना किया और उनको हराने का काम किया। मगर वे दोनों एक होकर चल रहे हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 1962 के बाद, मैं यह सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वर्ष 1962 के बाद, जीडीपी के सबसे कम प्रतिशत में डिफेंस का बजट दिया गया है, जो पिछले साल जीडीपी का केवल 1.9 प्रतिशत दिया गया। वर्ष 1962 से डिफेंस का बजट हमेशा जीडीपी का 2 प्रतिशत रहा है।

किरेन जी, यह स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, वर्ष 2013-14 में जीडीपी का 2.5 प्रतिशत हम डिफेंस पर खर्च कर रहे थे। यह धीरे-धीरे से घटकर 2 प्रतिशत हुआ और अब 1.9 प्रतिशत पर है। इसमें एक चिंता की बात यह भी है कि केवल डिफेंस के बजट में ही गिरावट आयी है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें कैपिटल आउटलो 30 प्रतिशत से भी कम है। मॉडर्नाइजेशन के लिए जितना बजट चाहिए, उतना बजट नहीं है। रिपोर्ट कार्ड हम क्या दें? एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने कहा कि टाइमलाइन एक बहुत बड़ा इश्यू है। कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाता है। हमारी सरकार को इसे देखना ही पड़ेगा। हम कोई ऐसा प्रॉमिस क्यों करते हैं, जिसे पूरा ही न कर पाएं। डेप्युटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहुल सिंह ने कहा कि जो इक्विप्मेंट्स जनवरी में डिलीवर होने थे, वे आज तक नहीं हुए। अगर वे डिलीवर हो जाते, तो ?ऑपरेशन सिन्दूर? में कहानी कुछ और होती। उन्होंने यह पब्लिक फोरम पर कहा और आप डिफेंस का बजट घटा रहे हैं।

डिफेंस बजट के मामले में, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। आप इसमें अग्निवीर योजना ले आए, जिसमें हमारे देश की फौज को कितना नुकसान हुआ, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं।

इसके साथ ही, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आपने एयरफोर्स मॉर्डनाइजेशन का बजट भी घटा दिया है। आज एयरफोर्स को 60 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। मगर यूपीए सरकार के समय 42 स्क्वाड्रन्स थी, आज उनकी संख्या घटकर 31 रह गई है। एक स्क्वाड्रन में 18 से 24 हवाई जहाज होते हैं। आज कई स्क्वाड्रन्स में जगुआर जैसे जहाज हैं। दुनिया के तमाम मुल्कों में इस जहाज को रिटायर कर दिया गया है। नाइजीरिया, अर्मेनिया, फ्रांस, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका इत्यादि देशों में जगुआर जहाज थे, उनको रिटायर कर दिया गया है। अभी हमारे देश में 60 की बजाय 31 स्क्वाड्रन्स हैं, लेकिन आपने जगुआर जहाज को रिटायर नहीं किया है। इस साल तीन जगुआर जहाज क्रैश हुए हैं, जिनमें से दो क्रैशेज़ में हरियाणा के जांबाज पायलट्स ने अपनी शहादतें दी हैं। हम उनको नमन करते हैं। जब मैंने उनके परिवार वालों से बात की, तब उनके परिवार वालों की जुबान पर एक ही बात थी कि आप सरकार से आग्रह करिए कि वह एयरफोर्स मॉर्डनाइजेशन की तरफ बढ़े। वह नए एयरक्रॉफ्ट्स लाए, इसमें हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन आपने एयरफोर्स मॉर्डनाइजेशन के बजट में कटौती कर दी है। डिफेंस के बजट में भी कटौती कर दी है और आप फौज के पराक्रम का नाम लेते हैं।

दूसरा, मैं कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कृषि क्षेत्र में एमएसपी का एक बड़ा प्रश्न है। यूपीए सरकार के समय एमएसपी में धान और गेहूं में औसतन प्रतिवर्ष 12 और 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। चाहे उड़द हो या मूंग दाल

हो, उसमें औसतन प्रतिवर्ष 20 और 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। एनडीए या आपकी सरकार के पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में अनाज में औसतन बढ़ोतरी 12-13 प्रतिशत थी और दाल में औसतन 20-22 प्रतिशत बढ़ोतरी थी, वह घटकर पांच और छः प्रतिशत हो गई है। धान में प्रतिवर्ष छः प्रतिशत और गेहूं में प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत कटौती हुई है। इसी तरीके से दालों में छः और आठ प्रतिशत कटौती हुई है। अगर हम इसको महंगाई दर से सब्सिट्यूट करें, तो आप यह मानिए कहीं न कहीं यह न के बराबर है। आप जो एमएसपी घोषित कर रहे हैं, वह किसानों को नहीं मिल रही है।

आपने इस साल धान पर 2,390 रुपये की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित की है। आप हरियाणा की मंडियों में जाकर देखिए, धान 1,500 से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, जो एमएसपी से कम है। आपने इस वर्ष बाजरा में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रुपये प्रति क्विंटल किया है, मगर बाजरा 1,800 या 1,900 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। कई जगहों पर बाजरे में एमएसपी भी नहीं मिली है। आपने कपास में 8,100 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी घोषित की थी, मगर मंडियों में 6,500 या 7,200 रुपये प्रति क्विंटल यानी किसान एमएसपी से कम मूल्य पर कपास बेचने के लिए मजबूर हुआ है। आज एमएसपी नहीं मिल रही है। यूपीए सरकार के समय जितना दाम बढ़ा था, आप प्रतिवर्ष उससे आधे से भी कम मूल्य दे रहे हैं। आप उसका जितना दाम बढ़ाकर घोषित भी कर रहे हैं, कितने किसानों को एमएसपी मिल रही है? आपको हरियाणा और पूरे देश का किसान उसके बारे में बता देगा।

आपने अनुदानों की अनुपूरक मांगों में कहा है कि हम खाद देंगे। मैं एक और बात कहना चाहूंगा। आप ?आत्मनिर्भर भारत? की बात करते हैं। मैं कपास की बात बता रहा हूं। आपने इस वर्ष कपास में 11 प्रतिशत की आयात ड्यूटी खत्म कर दी है। कपास विदेश से आ रहा है। हमारे देश में कपास पैदावार करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। आप ये ?आत्मनिर्भर भारत? का मॉडल देश के सामने रख रहे हैं। इसी तरीके से खाद की बात है। मैं लगातार पूरे देश और हरियाणा में देख रहा हूं कि खाद थानों में बिक रही है। हरियाणा में खाद पाने के लिए लाइन लगती है। वहां कभी लाठी चार्ज होता है, सरकार किसान के हाथ पर एक मोहर लगाती है कि वह लाइन में लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है।

एक बात किसान और मजदूर की बात है। हमारे एक साथी ने लोक सभा में एक आतारांकित प्रश्न पूछा था, इस हफ्ते उस प्रश्न का उत्तर मिला है। उस प्रश्न के अनुसार मनरेगा की क्या स्थिती है? मैंने किसान की बात की है। मैं मजदूर की भी बात बताऊंगा। मनरेगा की क्या स्थिति है? आप उसका अंदाजा लगाइए। आज हरियाणा में 8,00,000 मजदूरों ने मनरेगा में रजिस्टर कराया हुआ है। मगर पिछले वर्ष मात्र 2,100 मजदूरों को 100 दिन का काम मनरेगा के तहत मिला है। आप अंदाजा लगाइए कि यह स्थिति है।

तीसरा, अब मैं खेल जगत के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। श्री किरेन रिजिजू जी, खेल मंत्री रह चुके हैं, वह भी मेरी बात सुनें। इसमें बड़ी विडंबना है। आपने ?खेलो इंडिया? में 3,500 करोड़ रुपये का बजट रखा है। उस बजट में कुल मिलाकर हरियाणा को 80 करोड़ रुपये मिले हैं, पूरे देश की तुलना में सबसे कम बजट मिला है। ?खेलो इंडिया? के तहत गुजरात को 600 करोड़ रुपये का सबसे अधिक बजट मिला है। देश में जिस प्रदेश के खिलाड़ी सबसे ज्यादा मेडल्स

जीतते हैं, ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के 50 प्रतिशत खिलाड़ी मेडल्स जीतते हैं। ?खेलो इंडिया? में सबसे कम बजट उनके लिए हैं और आपने सबसे ज्यादा बजट गुजरात को दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरात में होंगे। अहमदाबाद में लाखों-करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अब तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि वहां ओलंपिक गेम्स भी कराएंगे।

मेरी सरकार से मांग है कि हरियाणा को इसके को-होस्ट के रूप में लिया जाए। भूपेन्द्र यादव जी यहां मौजूद हैं। यह मैं उनसे भी कहना चाहता हूं। धर्मेन्द्र जी भी हरियाणा के प्रभारी रहे हैं। उन्हें भी हरियाणा के बारे में पता है। आपको हरियाणा को कम से कम को-होस्ट बनाना चाहिए, बल्कि उससे तो होस्ट कराना चाहिए था ताकि लाखों-करोड़ों के खर्च में से कुछ खर्च हरियाणा के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हो। आपने देखा होगा कि बास्केट बॉल कोर्ट के अंदर हमारे खिलाड़ियों की जान तक जा रही है। खेल ढांचे की यह दुर्दशा है। ऐसा करने से आने वाले समय में आप हरियाणा के खेल ढांचे में इतना निवेश करेंगे कि हरियाणा, जो आज पूरे देश के 50 प्रतिशत मेडल्स लेकर आता है, आने वाले समय में हरियाणा के खिलाड़ी देश का गौरव और बढ़ाने का काम करेंगे। यह मेरी मांग है।

मुझे अन्य बहुत सारी बातें भी रखनी थीं, मगर मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि मुझे याद है कि वर्ष 2014 में जब एनडीए सरकार का पहला वर्ष था और स्वर्गीय माननीय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे। मुझे उनके पहले बजट की स्पीच याद है। उनकी उस समय की बजट स्पीच मुझे इसलिए याद है, क्योंकि उस समय विपक्ष की तरफ से मैंने ही बजट स्पीच पर इनिशिएट किया था। अपनी बजट स्पीच में उन्होंने कहा था ? ?Economy is ready to take off?. तब एवरेज ग्रोथ आठ प्रतिशत थी, जो अब घटकर साढ़े पांच प्रतिशत पर आ गई है। Ready to take off यानी हमारी अर्थव्यवस्था यूपीए के बंधनों से मुक्त हो चुकी है और अब टेक ऑफ की तरफ जा रही है। अब 11-12 सालों में वह टेक ऑफ हुआ या जहाज अभी रनवे पर ही खड़ा है, वह एयरपोर्ट्स पर हमारे यात्रियों ने देख लिया है कि क्या स्थिति बनी है। ? (व्यवधान)

वित्त मंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन विषयों पर ध्यान देंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : हम लोग ध्यान से सुन रहे थे। वर्ष 2005 में उनका जो पहला भाषण था, मैंने वह भी सुना है। ? (व्यवधान)

आपने एग्रीकल्चर पर बोला है। एग्रीकल्चर पर बोलते-बोलते मुझे याद आया कि उस समय सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ अपोजीशन थीं। उन्होंने आपको एक ज्ञान दिया था, मुझे वह याद आ गया। आप तैयारी करके नहीं आए हैं। आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर न बोलकर, बजट की चर्चा, जो पहले ही हो चुकी है, उस पर बोले हैं। यह सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, आप इस पर नहीं बोले हैं। खेल के बारे में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खिलाड़ियों में

झगड़ा मत करवाइए। खेल बहुत आगे बढ़ रहे हैं, खेलो इंडिया कार्यक्रम चल रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है। आप झगड़ा मत लगाइए।? (व्यवधान)

CUT MOTIONS

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): I beg to move:

(TOKEN)

THAT THE DEMAND FOR A SUPPLEMENTARY GRANT OF A SUM NOT EXCEEDING RS.1303,73,00,000 IN RESPECT OF DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION (PAGE 27) BE REDUCED BY RS.100.	**26**
Need to provide more funds for strengthening higher education system at the State-level. (1)	
Need to check implementation of a centralized digital framework in respect of linguistic diversity and State autonomy in higher education under the ? Pradhan Mantri One Nation One Subscription (PM-ONOS)? scheme. (2)	
Need to provide more funds and ensure equitable distribution of funds across State universities *vis-a-vis* centrally-controlled World Class Institutions. (3)	
THAT THE DEMAND FOR A SUPPLEMENTARY GRANT OF A SUM NOT EXCEEDING RS.7,00,000 OF MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (PAGE 60) BE REDUCED BY RS.100.	**60**
Need to address persistent concerns about inequitable funding under the Smart Cities Mission, where cities of different States including Tamil Nadu have repeatedly reported delays in	

approvals, shortfalls in releases and restrictions placed by the Union on project flexibility. (4) Need to ensure adequate allocations for rental housing, slum redevelopment and low-cost housing projects. (5) Need to prioritise Electric Vehicle (EV) infrastructure grants for cities across the country including Chennai which is one of India?s largest EV manufacturing hubs. (6)	
THAT THE DEMAND FOR A SUPPLEMENTARY GRANT OF A SUM NOT EXCEEDING RS.6,00,000 OF DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (PAGE 64) BE REDUCED BY RS. 100. Need to address the delays on the Godavari? Cauvery interlinking project which is crucial for Tamil Nadu?s long-term water security. (7) Need to address Tamil Nadu?s long-standing concerns on equitable water sharing of inter-state rivers to ensure compliance by upper riparian States. (8) Need for targeted allocations to modernize Tamil Nadu?s irrigation systems, particularly the Cauvery delta?s ageing canal network. (9) Need to allocate funds for rejuvenation of Cauvery, Vaigai and Thamirabarani rivers. (10)	**62**
THAT THE DEMAND FOR A SUPPLEMENTARY GRANT OF A SUM NOT EXCEEDING RS.1,00,000 DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND	**63**

SANITATION (PAGE 67) BE REDUCED BY RS.100.

Need to provide sufficient funds under the Jal Jeevan Mission to states like Tamil Nadu which has consistently exceeded national performance benchmarks but continues to face delayed release of central funds. (11)

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): I beg to move:

(TOKEN)

THAT THE DEMAND FOR A SUPPLEMENTARY GRANT OF A SUM NOT EXCEEDING RS. 1303,73,00,000 OF DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION (PAGE 27) BE REDUCED BY RS. 100. **26**

Need to establish a 'Innovation and Startup Capacity Grant' to be disbursed directly by world class Central Universities to their affiliated technical colleges especially Tier 2 and Tier 3 colleges. (14)

THAT THE DEMAND FOR A SUPPLEMENTARY GRANT OF A SUM NOT EXCEEDING RS. 2,00,000 OF DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (PAGE 44) BE REDUCED BY RS. 100. **46**

Need for mandatory inclusion of high-cost Outpatient Treatment (OPD) for chronic and catastrophic diseases underthe Ayushman Bharatcheme. (19)

THAT THE DEMAND FOR A SUPPLEMENTARY GRANT OF A SUM NOT EXCEEDING RS. 27,16,00,000 OF DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH (PAGE 45) BE REDUCED BY RS. 100. **47**

Need for a dedicated and adequately funded national research initiative to systematically study the direct

correlation between environmental carcinogens (air pollution, contaminated water, industrial effluents) and the increasing incidence of cancer in various regions of India. (20)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य - श्री जगदम्बिका पाल जी।

? (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत हमारे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जो वर्ष 2025-26 का फर्स्ट बैच है, उस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। ? (व्यवधान) मैं कुछ कहूं, उसके पहले संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी ने कह दिया है कि यह सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, लेकिन हमारे हुड्डा जी निश्चित तौर से सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर कम बोले हैं और बजट पर ज्यादा बोले हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं इसे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के पहले बोलना चाहता हूं। निश्चित तौर से, आखिर इस सदन के माध्यम से उन्होंने जो बात उठाई है और वह उस पक्ष की तरफ से कही जाए, तो कम से कम वह तथ्यात्मक होनी चाहिए और सही भी होनी चाहिए।

महोदया, उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) ने भारत की इस इकॉनमी या उसके ग्रोथ के बारे में की आलोचना की है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं कि आईएमएफ ने, जिसकी रिपोर्ट में ?सी? ग्रेडिंग है, शायद वह ?सी? ग्रेडिंग किसी विकास दर या किसी डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाता है। इनकी सरकार में वर्ष 2011 और वर्ष 2012 में जो बेस इयर था, वह ग्रेडिंग उसमें थी। मैं चुनौती के साथ यह कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि आज इन्फ्लेशन के मामले में, गवर्नमेंट के फाइनेंस के मामले में और एक्सटर्नल सेक्टर के मामले में भारत को ?बी? ग्रेड मिला है, जो चाइना और ब्राजील के बराबर है, जिसकी बात दुनिया करती हैं। ? (व्यवधान) यह मैं चुनौती देकर कह रहा हूं।

15.00 hrs

आज भारत को बी-ग्रेड मिला है। चीन, जिसका उदाहरण उनके नेता सबसे ज़्यादा देते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर भी होगा, तो उनके एंबैसडर के साथ बैठेंगे, चीन की तारीफ़ भी करेंगे। आज ये भी तारीफ़ कर रहे थे कि चीन और पाकिस्तान एक हो गया है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जो भारत की इकॉनॉमी है, it is becoming the fastest growing economy.

आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप इकॉनॉमी की बात करते हैं। आज कोई इकॉनॉमिक स्लोडाउन नहीं है। हुड्डा जी, आप जाइए मत। जिस समय आपकी सरकार थी, उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो वर्ड्स थे कि

इस देश में पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था। वह उस नीति की पंगुता थी। जो लोग एफडीआई ला रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस अब डिस्कस नहीं हो रहा है। अब एफ़.डी.आई. का इन्वेस्टमेंट वापस नहीं जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह कांग्रेस/यूपीए सरकार में इकॉनॉमिक स्लोडाउन और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण एफ़.डी.आई. वापस जा रही थी, आज भारत इकॉनॉमिक एक्सीलरेशन की तरफ है। इसलिए आज इंडिया की फाइनेंशियल ईयर की विकास दर 8.2 परसेंट ग्रोथ रेट है, जो दुनिया में सबसे तेज़ है, नंबर एक पर है।

आज आप इंडिया की जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि इंडिया की ग्रोथ रेट 8.2 प्रतिशत है। आप यू.एस.ए. की बात करते हैं और आपने कहा कि वहां की इकॉनॉमी डीओ पॉलिसी और मोनो पॉलिसी के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार है। ? (व्यवधान) धर्मेन्द्र जी आप मेरी बात सुनिए। आप कहते हैं कि मोनोपॉली के खिलाफ कानून बनाने की बात करते हैं। आज इंडिया की 8.2 परसेंट ग्रोथ रेट है, लेकिन यूएसए की जीडीपी केवल 3.8 परसेंट है। यह मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। चीन की जीडीपी 5.2 परसेंट, रूस की 1.1 परसेंट पर है। आज दुनिया के जो चार बड़े देश हैं, उनमें यूएसए, चीन, रूस हैं। अगर रूस 1.1 परसेंट पर है, चीन 5.2 परसेंट पर है, यूएसए 3.8 परसेंट है, तो भारत की जीडीपी 8.2 परसेंट है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करता हूं।

फाइनेंशियल ईयर 2026 का यह क्वार्टर 8.1 परसेंट है। मैं कह रहा हूं कि आज सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स इसलिए आई हैं,क्योंकि इसका कारण है। आज हमने इसमें कठोर वित्तीय अनुशासन किया है, समावेशी विकास किया है। जो मोदी जी की पार्ट-3 सरकार है, वह एक निर्णायक और परिणामकारी सरकार है। हुड्डा जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह आईएमएफ ने नहीं कहा है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि आईएमएफ ने ही, जिसके नाम का आप उल्लेख कर रहे हैं, उसी ने भारत की ग्रोथ की तारीफ़ की है। आईएमएफ खुद कह रहा है कि भारत फाइनेंशियल ईयर, 2026 में 6.5 की रेट से बढ़ेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्टेबल माइक्रो-इकॉनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत होगी। यह आईएमएफ की रिपोर्ट है। यह फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से मजबूत है। यह कहना कि भारत का डेटा गलत है। आप एक तरफ आईएमएफ का उल्लेख करेंगे और फिर उसके नाम से आप कहेंगे कि आईएमएफ आलोचना कर रहा है। यह आईएमएफ की ही तारीफ़ है।

मैं कहता हूं कि अगर आप वास्तविक ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो कम से कम आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ लेते, तभी बोलते। आज आप आईएमएफ का हवाला देकर देश के सामने गलत तस्वीर खींचना चाहते हैं, वह टिक नहीं सकती है। भारत ने क्वार्टर-1 में 7.8 परसेंट की ग्रोथ रेट पाई गई है और क्वार्टर-2 में 8.2 परसेंट की ग्रोथ है। अभी पुतिन भारत आए थे और उन्होंने तारीफ़ की। रूस के राष्ट्रपति ने तारीफ़ की है। आज जो कह रहे थे कि भारत और रूस की इकॉनॉमी डैड हो जाएगी, लेकिन ऐसे पश्चिमी देश के राष्ट्रपति भी फिर से भारत के प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। इससे साबित हो गया है कि पूरी दुनिया भारत के साथ रिश्ता रखना चाहती है और उसके साथ ट्रेड में आना चाहती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह 6 महीने की रिपोर्ट है, इसी पर सवाल है।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था? राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 100 पैसा यहां से भेजते हैं और गांव में बेनिफिशियरी को 15 पैसा पहुंचता है। यह मेरा कहना नहीं है, यह हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी का कहना था। उस समय 100 रुपये भेजते थे, तो 15 रुपये पहुंचते थे और एक रुपया भेजते थे, तो 15 पैसा पहुंचता था। आज नरेंद्र मोदी 100 रुपये भेजते हैं, तो 100 रुपये लाभार्थी के पास पहुंच रहा है। मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। ? (व्यवधान) आज जिस आईएमएफ का हवाला दे रहे हैं और धर्मेन्द्र जी आप भी इस बात को कोट करते थे। राजीव गांधी जी की बात आप भी और अखिलेश यादव जी भी कोट करते थे। वे खुद ही कहते हैं कि हम पैसा भेजते हैं, लेकिन पैसा पहुंचता नहीं है। यह मिडिल मैन की वजह से है।

उस मिडिलमैन, बिचौलियों को दूर कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम दुनिया में पहली बार भारत में लागू करके बिचौलियों को हटाकर सरकार से पैसा सीधे उनके खातों में जाएगा। चाहे वह महिला के खाते में जाए, चाहे पुरूष के खाते में जाए, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो या जो भी स्कीम्स हों। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि कलानिधि जी वह आईएमएफ की ही रिपोर्ट है। यह मामूली बात है, देश वर्ष 1947 में आजाद हुआ और 11 वर्षों में आप कह रहे हैं बीपीएल, गरीबी रेखा में डाल दिया। आज पूरा विश्व आश्चर्यचकित है, मोदी जी जहां दुनिया के अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन में जाएं, जी-20 में जाएं, चाहे सार्क में जाएं, चाहे दाओस के सम्मेलन में जाएं, चाहे ब्रिक्स में जाएं या किसी सम्मेलन में जाते हैं, तो दुनिया पूछती है कि भाई पिछले दस वर्षों में आपने भारत में 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा में से कैसे निकाला? आज वे बीपीएल से एपीएल में पहुंचे हैं।? (व्यवधान) आनंद जी, कुछ अपना ज्ञान वर्धन कीजिए, कुछ समझिए, ज्ञान वर्धन करने की कोशिश कीजिए। आखिर क्या आज सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट पहली बार आयी हैं? धर्मेन्द्र जी, 15वीं लोक सभा में भी थे, जब कांग्रेस-यूपीए की सरकार थी, तब भी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आती थीं, डिमांड फॉर ग्रांट्स आती थीं। अंतर क्या है? उस समय जब डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आती थीं, तो वह जो एक्चुअल बजट में नहीं होता था और उसको फोर्स ही नहीं करते थे। यह एक फायनेंसियल प्रक्रिया है कि सरकार उसको सप्लीमेंट्री में लाती है, लेकिन उस समय एक वे के रूप में ही लाते थे कि हमको यह खर्चा चाहिए, हमको यह खर्चा चाहिए। आज 1.3 लाख करोड़ की जो हम सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट ला रहे हैं, उसमें 31 परसेंट ही केवल नगद व्यय ले रहे हैं, 69 परसेंट, हमारा जो वित्तीय अनुशासन है, डिपार्टमेंट की जो सेविंग्स होंगी उस सेविंग से हम सप्लीमेंट्री ला रहे हैं, यह पहली बार इतिहास बनाने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि 69 परसेंट? (व्यवधान) आप पूरी बात सुन लीजिए, तब आप कोई प्रश्न पूछेंगे, मैं उत्तर दे दूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट हैं, इसके पीछे क्यों हैं? मैं कहता हूं कि आप किसान की बात करते हैं और हमने किसान के लिए सप्लीमेंट्री लिया है। अगर मांगा है तो किसलिए मांगा है? ओझला साहब एक्सपेंडिचर के लिए नहीं मांगा है। हम उसको निवेश समझते हैं। आप समझते होंगे कि अगर किसानों पर पैसा खर्च करना सरकार का खर्चा है, लेकिन मोदी की सरकार समझती है कि किसान पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वह भारत का निवेश है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी हुड्डा साहब उर्वरक की बात कह रहे थे वर्ष 2025-26 के मूल बजट में केवल किसानों की सब्सिडी के लिए एक लाख सड़सठ हजार आठ सौ सत्तासी करोड़ का प्रावधान किया था। यह किसानों की सब्सिडी के लिए था और आज एलाइड सेक्टर्स मिलाकर एक लाख

इकहत्तर हजार करोड़ रूपये का प्रावधान था और हमने सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में फर्टिलाइजर के लिए 31 हजार 66 थे, जिसमें 19 करोड़ लिए हैं। यह फर्टिलाइजर के लिए है। अगर किसान को फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी देनी है, तो उस फर्टिलाइजर की सब्सिडी अगर हम दे रहे हैं, तो उसका नतीजा भी है कि यह जो हम दे रहे हैं आज उसी का नतीजा है कि वर्ष 2015-16 में जब आपकी सरकार थी, तो उस समय 251.54 मीट्रिक टन खाद्यान हुआ था और आज वर्ष 2024-25 में 2 लाख 51 हजार मीट्रिक टन से 3 लाख 57 हजार मीट्रिक टन पैदावार बढ़ी है, जो दुनिया में एतिहासिक है। आज आप देख रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में हमारा खाद्यान 8 परसेंट बढ़ गया है, तो आज यह देन इसलिए है कि हम किसानों को खाद पर सब्सिडी दे रहे हैं। आज यह देन इसलिए है कि जो किसान गांव में रहता है, स्मॉल फॉर्मर्स, मार्जिनल फॉर्मर्स, सभापति महोदया, आप भी गांव से आती हैं, उन किसानों के पास सिंचाई का पैसा नहीं रहता है, उनके पास पेस्टिसाइड खरीदने का पैसा नहीं रहता है, उनके पास कीटनाशक दवाओं के लिए पैसा नहीं रहता है। दुनिया में पहली बार कोई सरकार आयी है, जिसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान के नाम पर छह हजार रूपया किसानों को देने का काम किया है, लागत देने का काम किया है।

इसलिए आज खेती पर लागत कम हो रही है। आज खेती पर लागत कम हो रही है और उत्पादन ज्यादा हो रहा है। आज हम फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी दे रहे हैं, हो सकता है कि आप इसकी आलोचना करें, लेकिन हमें संतोष है। हम जो पैसा सब्सिडी पर दे रहे हैं, यह किसानों के लिए इनवैस्टमेंट है, उनके लिए निवेश है। उनकी क्षमता से देश की खाद्य सुरक्षा हो, वह अपने आप में एक मजबूती का प्रतीक है। कृषि मंत्रालय ने अभी वर्ष 2024-25 का नवीन आंकड़ा जारी किया है। उसमें 357.73 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, जबकि इनके जमाने में 251.54 मिलियन टन हुआ था।

हम लोग दलहन, तिलहन के लिए इसी सदन में रोज कहते थे कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पल्सेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑयलसीड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में तिलहन का उत्पादन 39.76 मिलियन टन हुआ था, पिछले साल जहां 39.67 मिलियन टन तिलहन पैदा हुआ था, वही वर्ष 2024-25 में 43 मिलियन टन की पैदावार हुई है और यह इस देश के किसान के कारण हुई है। यह जो वृद्धि हो रही है, प्रधान मंत्री मोदी जी का जो ऑयलसीड का मिशन है, यह उसकी सफलता का प्रतीक है। अगर दालों में आत्मनिर्भरता होती है, तो उस दिशा में यह कितनी बड़ी सफलता है।

ये डॉ. स्वामीनाथन की बात करते थे। स्वामीनाथन आयोग तो आपने ही बनाया था कि कृषि की आय को कैसे दुगुना किया जाए। इसके लिए आपने वर्ष 2005 में स्वामीनाथन आयोग बनाया था। आपने कृषि आय के लिए उनको कहा और उन्होंने रिपोर्ट दे दी। कांग्रेस, यूपीए की सरकार ने डॉ. स्वामीनाथन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी। मैं देश के किसानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश का जनादेश नरेन्द्र मोदी जी को मिला और उन्होंने डॉ. स्वामीनाथन की रिपोर्ट को देश में लागू करने का काम किया है, जिससे आज देश के किसानों को फायदा हो रहा है। उन्होंने तय किया कि हम देश के किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, उनका जो उत्पादन मूल्य होगा, वह उससे डेढ़ गुना होगा और उनको आज तो उनके उत्पादन मूल्य से दोगुना मिल रहा है। यह स्वाभाविक है कि यह डॉ. स्वामीनाथन की रिपोर्ट की देन है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं, यह कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है। यह कोई दस्तावेज नहीं है। यह किसानों को इम्पावर्ड करने और सशक्तीकरण करने का बिल है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पारित करें। इस बिल का यह उद्देश्य है कि किसानों के उत्पादन की लागत में कमी आए। किसानों की आय बढ़ाना हमारा काम है और सरकार की तरफ से फर्टिलाइजर्स को सुनिश्चित कराना हमारा काम है। अगर हम इसके लिए कृत संकल्प हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये इस बात पर बधाई नहीं देंगे। मैं सबसे पहले कहता हूं, किसान ने खाद्य की सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरह से काम किया है, इस देश का जो सेंट्रल पूल होता है, जुलाई, 2025 में उस पूल में 377.83 लाख टन चावल है, 358.78 लाख टन गेहूं है। सेंट्रल पूल में गेहूं और चावल का इतना बड़ा भंडार कभी नहीं रहा है, जो आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में है। जो निर्धारित मानक है, यह उससे कई गुना ज्यादा है और यही भंडार काम आ रहा है। इनको यही इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत प्रधान मंत्री जी किस तरह से 81 करोड़ लोगों को कोविड के जमाने से 5 किलो खाद्यान्न परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को दे रहे हैं। आज तक इनको यह इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आई। क्योंकि भारत सरकार ने एक तरह से गेहूं और चावल का अपार भंडार रखा है, इसलिए हम यह लगातार दे रहे हैं। लोग कहते थे कि कोविड के कारण यह दे रहे हैं, चुनाव के लिए दे रहे हैं और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट खत्म हो जाएगा। आज 6 साल हो गए हैं, वर्ष 2019 से आज वर्ष 2025 हो गया है, आज भी गांव में किसी जाति, बिरादरी, गरीब या जो भी लोग हैं, सबको 5 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति के हिसाब से उनके परिवार को मिल रहा है। अगले पांच सालों के लिए इस पर 11.80 लाख करोड़ रुपये सरकार व्यय करेगी। मैं समझता हूं कि हुड्डा जी को इस पर बधाई देनी चाहिए थी, क्योंकि वह खुद हरियाणा से किसान परिवार से आते हैं। यह सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी है और दुनिया में इतनी बड़ी कोई फूड सिक्योरिटी नहीं है, जो गरीब व कमजोर वर्गों के जीवन में स्थिरता और गरिमा लाती है।

मैं पशुपालन की बात करना चाहता हूं। मैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर ही बात कर रहा हूं, मैं इधर-उधर कहीं नहीं जा रहा हूं।

आज पशुपालन और ग्रामीण अवस्था में भारत का वास्तविक अधिकार सेरीकल्चर है, हॉर्टीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हसबेंडरी है, फिशरीज़ है, जिसको ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं, जिसको जीरो आवर में उठाया जा रहा था। मैं कह रहा हूं कि आज पशुपालन हो, डेयरी हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, उसको मजबूत करने के लिए इस सप्लीमेंट्री में, इस डिमांड फॉर ग्रांट्स में हम नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, ब्रीड इम्प्रूवमेंट इंस्टीट्यूट और भारत के दूध उत्पादन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन ले रहे हैं। हम नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के लिए 361 करोड़ रुपये, ब्रीड इम्प्रूवमेंट और दूध उत्पादन के लिए 146.30 करोड़ रुपये ले रहे हैं। वर्ष 2014-15 दूध का उत्पादन 146.36 मिलियन टन था। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 239.30 मिलियन टन हो चुका है। इस तरह 63.50 प्रतिशत दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। आज मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में भारत सबसे बड़ा दूध का उत्पादक हो गया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इसके लिए नीतियां है। यह नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में चले ब्रीड के इम्प्रूवमेंट के लिए हैं कि जानवरों की ब्रीड का इम्प्रूवमेंट कैसे हो, उसके लिए चले। इसी नाते आज मवेशियों की उत्पादकता में 27.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जहां तक अभी ऊर्जा सुरक्षा की बात हो रही है, भले ही इनको न लगता हो, क्योंकि इन्हें अहसास नहीं है, पर मोदी जी ने गरीबी देखी है। उन्होंने देखा है कि महिलाओं को ईंधन में काम करने में, लकड़ी के चूल्हे पर काम करने में कठिनाई होती है। जब वे एक वक्त का खाना पकाती थीं, तो 400 सिगरेट का धुंआ जाता था। आज उन्होंने उस कष्ट को देखा, बचपन में अपनी मां को देखा, अपने परिवार को देखा। इसलिए आज उन्होंने तय किया कि दुनिया में जो गरीब है, आखिर उसका क्या गुनाह है? गांव में या सुदूर अंचल में रहने वाले को भी क्लीन एनर्जी मिले, उसको अपना भोजन चूल्हा, कंडा, लकड़ी पर न बनाना पड़े, उसके लिए उज्ज्वला योजना लागू करके, उसको भी एक स्वच्छ ईंधन देने का काम किया है, तो आज मुझे लगता है कि इन योजनाओं के लिए यदि हम डिमांड ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में पैसा मांग रहे हैं, तो आपको तो तारीफ करनी चाहिए। हमारी उज्ज्वला 2.0 योजना हुई, जिसमें मूल बजट में 12,100 करोड़ रुपये की सब्सिडी निर्धारित थी। अब पीएम उज्ज्वला योजना में उसकी जो बढ़ती हुई सफलता है, जो ग्रामीण और शहरी, लाखों परिवारों की आवश्यकता है, यदि उसको ध्यान में रखते हुए अपने देश के गांवों में रहने वाली वे गरीब महिलाएं, जिनके घर में आज तक यह चूल्हा नहीं पहुंचा था, यह फ्री सिलेंडर नहीं पहुंचा था, अगर वह गैस का चूल्हा और सिलेंडर दे रहे हैं और उसके लिए हम सप्लीमेंट्री मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज देश की करोड़ों महिलाएं इसका स्वागत करेंगी, जो हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लेकर आई हैं। इसके लिए हमने सप्लीमेंट्री डिमांड्स में 14,692 करोड़ रुपये मांगे हैं कि 14,692.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रबंध किया जाए। इसमें जो नकद व्यय होगा, वह 9,473.44 करोड़ रुपये का होगा। दुनिया में कोई इतनी बड़ी योजना नहीं होगी। पीएम उज्ज्वला योजना में करीब 11 करोड़ महिलाओं के घरों में धुंआ रहित रसोई का प्रबंध किया गया है। इसकी सराहना आज केवल हम या हमारी सरकार ही नहीं कर रही है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि जो भारत में प्रधान मंत्री मोदी जी ने पीएम उज्ज्वला योजना लागू की है, इससे बड़ी मेजर हैल्थ इंटरवेन्शन पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वह तो पूरी दुनिया का मूल्यांकन करता है। मैं केवल भारत की तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं अपने साउथ-ईस्ट एशिया के मुल्कों, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से इसकी तुलना नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदया, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं कि आज डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि यह दुनिया में सबसे बड़ा मेजर हैल्थ इंटरवेन्शन है। आज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या कहती है? वह सबसे बड़ी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। वह कहती है कि इस योजना से इतना बड़ा सोशल और इकॉनोमिक एचीवमेंट आया है, जो आज सीधे लाभार्थियों के घरों में गया है। महिलाओं का स्वास्थ्य सुधरा है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं। इसकी वजह से सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आया है। जो महिलाएं एनिमिक होती थीं, अस्थमा की मरीज होती थीं, केवल इसलिए कि वे गीली लकड़ियों से अपने बच्चों, अपने सुहाग के लिए खाना बनाने के लिए चिमनियों की तरह से अपने कलेजे से लकड़ी जलाने की कोशिश करती थीं। इससे उनका चेहरा लाल हो जाता था और उनके सीने में परेशानी होती थी। आज उन महिलाओं का स्वास्थ्य सुधरा है।

जैसे पहले बड़ों के घरों में गैस का चूल्हा होता था, आज ये एक-एक गरीब के घरों में पहुंचा है। ये 11 करोड़ लोगों के घरों में पहुंचा है। पहले महिलाएं गांवों से जंगल में इंधन जुटाने के बाहर जाती थीं। वहां से वे लकड़ियां चुन कर लाती

थीं। उनको घरों से बाहर जाने में दिक्कतें होती थीं। इससे उन्हें समय में बचत हुई है। अब उनको इंधन जुटाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। इससे महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। इसलिए मैं एलपीजी सब्सिडी के लिए कहता हूं कि यह केवल आर्थिक प्रावधान नहीं है बल्कि यह महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और उनके न्याय का संवैधानिक विस्तार हुआ है। पीएसयूज, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनिज हैं, उनके जो अंडर-रिकवरीज हैं, उनको समेकित करके वितरण व्यवस्था को स्थिरता प्रदान किया गया है। इसलिए वैश्विक ऊर्जा के इतने उतार-चढ़ाव के बीच भारत की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक कदम है।

ऑपरेशन सिंदूर की बात कही गई है। देश की आजादी के बाद आज डिफेंस में क्या रेवोल्यूशन आया है, इसके बारे में हुड्डा जी नहीं कह रहे हैं। वे वर्ष 2005 के बारे में कह रहे हैं। रिजिजू जी ने इस पर बयान दिया है। मैं उनके ज्ञान के लिए कह रहा हूं कि आज रक्षा मंत्रालय का बजट 4,91,732 करोड़ रुपए है। आज देश में सर्वाधिक बजट रक्षा बजट का है। आज हम उसमें और सप्लिमेंट्री मांग रहे हैं। हम 4,577 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांग रहे हैं। यह भी हमारे वित्तीय अनुशासन और रणनीति के लिए है। मैं दस वर्षों के बारे में एक लाइन में जवाब दे दूंगा जिससे केवल आप ही नहीं बल्कि पूरा देश इस बात से सहमत होगा। आज भारत के रक्षा मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा उत्पादन में इतिहास रच दिया है। वर्ष 2014 की तुलना में आज डिफेंस प्रोडक्शन में 174 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। फाइनैंशियल ईयर 2024-25 में 1.54 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस में उत्पादन हो रहा है। कुछ सालों पहले तक हम हाई एलटिच्यूड का जूता भी बाहर से मंगाते थे। हम बैग्स मंगाते थे। हमारे यहां कैरी बैग्स नहीं थे। आप गोले-बारूद की बात छोड़ दीजिए। यह कहा जाता था कि यह चार दिनों के लिए है। हम विदेशों पर बहुत डिपेंडेंट थे। आज हम पहली बार नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज आप निर्यात को ले लीजिए। आप हिट एंड रन करके चले जाएंगे। वर्ष 2014 में आपका रक्षा निर्यात कितना था? वह एक हजार करोड़ रुपए का भी नहीं था लेकिन आज हम 23,622 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम ये इम्पोर्ट करते थे। हम डिफेंस के सारे इक्विप्मेंट्स बाहर से मंगाते थे। यहां हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी बैठे हैं, वे भी इंटरवीन करेंगे। आज हम ये इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम 23,622 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सरकार ने वर्ष 2029 तक का लक्ष्य रखा है कि हम रक्षा उत्पादन 23 हजार करोड़ रुपए से बढ़ा कर तीन लाख करोड़ रुपए करेंगे और इसमें से 50 हजार करोड़ रुपए का निर्यात होगा।

आप भारतीय नौसेना की बात करेंगे। भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए आईएनएस माहे है। प्रधान मंत्री जी पिछले दिनों वहां गए थे। नए स्वदेशी पनडुब्बियों की बात, उन्नत प्रणालियों की बात और आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कह रहे हैं। पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य का लोहा मान लिया है। राहुल गांधी भारतीय सेना से हिसाब मांग रहे थे, जिस समय भारतीय सेना और एयरफोर्स पाकिस्तान में घुस कर नौ-नौ आतंकवादी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर रहे थे, तबाह कर रहे थे। इससे पूरी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित थे। उस समय आप हमसे हिसाब मांग रहे थे। आज उस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है, उस समुद्री क्षमता की ऊचाईयों, स्काई रूट, इनफिनिटी कैम्पस, लिप इंजन एमआरओ फैसिलिटीज और एयरो स्पेस के रेडीनेस को देखा है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। वर्ष 2019 में भारत विश्व के उन चुनिंदा शक्तियों में शामिल हुआ है, जो अंतरीक्ष में भी एंटी सैटेलाइट की क्षमता रखते हैं।

भारत भी उन देशों में पहुंच गया है।? (व्यवधान) अभी शुरुआत है। हुड्डा जी नोट करिएगा। आप राहुल या प्रियंका से कह दीजिएगा, वे इसका जवाब देंगे।

आज भारत एंटी सैटेलाइट स्पेस में दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक हो गया है। भारत की लैंड, भारत की सी, भारत के एयर स्पेस, चारों आयामों में हमारा सुरक्षा ढांचा और सुद्ढ़ हुआ है।

आप वर्ष 2025-25 की बात करते हैं, आपने शिक्षा की बात ही नहीं की, हम शिक्षा के ऊपर कहना चाहते हैं। शिक्षा में कितना बड़ा रिवोल्युशन आया। वर्ष 2025-26 में सरकार ने शिक्षा को रणनीतिक प्राथमिकता रखा था। आपने बजट की बात की इसलिए मैं पहले बजट की बात करता हूं और फिर सप्लीमेंटरी डिमांड की बात करूंगा। मूल बजट में एक 1 लाख 28 हजार 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सभापति महोदया, प्राइमरी स्कूल तो चलवा नहीं पा रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदया, यह देख लीजिए, कितना महत्वपूर्ण है। आज सप्लीमेंटरी डिमांड किसलिए मांग रहे हैं? आज धर्मेन्द्र जी सप्लीमेंटरी डिमांड मांग इसलिए रहे हैं।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, जब आपका अवसर आएगा, तब अपनी बात रखिएगा।

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदया, आज हम सप्लीमेंटरी डिमांड वन नेशन, वन सबसक्रिप्शन और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के लिए मांग रहे हैं। भारत हायर एजुकेशन में दुनिया में कहीं नहीं था। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए वन नेशनल वन, सब्सक्रिप्शन के लिए 2023 करोड़ रुपये मांग रहे हैं, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के लिए 274 करोड़ रुपये मांग रहे हैं।

यह शिक्षा पर व्यय नहीं है, यह राष्ट्र की भविष्य की पूंजी है। आज पीएम ओएनवनएस में क्रांतिकारी मॉडल आया है। आज आप देखिए, हम कहां हैं? वर्ष 2010 में जो भारत वैज्ञानिक जर्नल निकलते थे, उसमें हम विश्व में सातवें स्थान पर थे, आज 2020 में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं, हमारे साइंटिस्ट के जर्नल निकल रहे हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, न कोई आईआईटी था। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2025 में भारत के 54 भारतीय विश्वविद्यालय और 12 आईआईटी वर्ल्ड की रैंकिंग में शामिल हैं। इसके लिए मैं नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता हूं।

वैश्विक मंचों पर भारत आज उच्च शिक्षा अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। डिमांड फॉर ग्रांट्स में किस तरह वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन हो और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन हो, यह हमारी सरकार की नीतियों का परिणाम है। आज भारत में शोधन और नवाचार में तेजी से उभर रहा है। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं बनते हैं। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के लिए एक इंटरनेशनल पैरामीटर्स होता है, इसके अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं। उस अंतर्राष्ट्रीय मानक में जब हमारा इंस्टीट्यूशन उनके साथ एट-पार आएगा, तब वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन्स उसकी रैंकिंग करते हैं।

अभी तक हम शिक्षा में कहीं नहीं थे। शिक्षा में इंटरनेशनल पैरामीटर्स को कम्पीट करके हमारे देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल लेवल पर एट-पार हों, उनकी रैंकिंग हों, उसके लिए एक-दो पैसा नहीं, 6199 करोड़ रुपये नरेन्द्र मोदी की सरकार ने खर्च किया है। तभी जाकर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन्स बन रहे हैं। भारत को एक पावरफुल एकेडमिक हाउस बनाने की कोशिश हो रही है।

हम लोग पहले अमेरिका और इंगलैंड पढ़ने जाते थे। आज हम एकेडमिक पावर हाऊस बनाना चाहते हैं। इसका श्रेय देश के वैज्ञानिकों और प्रोफेसर्स का है। सरकार ने बजट दिया, सरकार ने गाइडेंस दिया। आपने कोविड में देखा, प्रधानमंत्री जी खुद लेबोरेटरीज में गए, जहां दुनिया में किसी वायरस की दवा नहीं बनती थी, पहली बार दुनिया में हमने कोविड के एक नहीं दो-दो इंजेक्शन बनाए हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों को बधाई दीजिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, अनुसंधान का क्षेत्र हो, नवाचार का क्षेत्र हो, भारत आज उस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में एशिया का सबसे प्रमुख नवाचार कर्ता बन चुका है।

सभापति महोदया, समय का अभाव है इसलिए मैं शिक्षा का विषय छोड़कर विदेश नीति की बात करना चाहता हूं। इसी सदन में चाबहार पोर्ट की चिंता होती थी कि यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान रास्ता बंद कर दें तो भारत का पूरी दुनिया के साथ पानी द्वारा सम्पर्क कट जाएगा। हमने बजट 20517 करोड़ रुपये का किया है और सप्लिमेंटरी डिमांड भी 542 करोड़ रुपये की ले रहे हैं। जो चाबहार पोर्ट है, मारिशस हो, पेसिफिक आइसलैंड हो, इन देशों के साथ और पूरे सैंट्रल एशिया के साथ पूरे साल हमारा ट्रेड होता है, इसलिए हम सप्लिमेंटरी डिमांड्स ले रहे हैं। केवल आलोचना करने के लिए आप आलोचना करेंगे, यह उचित नहीं है। आज प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस तरह से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए हुए है। आज केवल प्रधान मंत्री जी ही विश्व के नेता नहीं बन रहे हैं, बल्कि भारत भी हिंद महासागर क्षेत्र का नैसर्गिक नेता बन रहा है।

महोदया, विकास की बात, कूटनीति की बात, सुरक्षा की बात हो, सरकार हर चीज में बैलेंस रख रही है और तीनों का संतुलन भारत के हाथ में है।

माननीय सभापति : जगदम्बिका पाल जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, मैं केवल एक मिनट का समय और लूंगा। जब टैरिफ लगा तो तमाम अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस टैरिफ का व्यापक असर पड़ेगा और इससे भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा लेकिन हम प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस विषय पर कभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। जिस तरह से हमारी सरकार ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, नए बाजार खोलना शुरू किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत और यूनाइटेड किंग्डम की, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, मैं उसके लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा। यह समझौता केवल भारत और यूनाइटेड किंग्डम का फ्री ट्रेड का नहीं होगा, यह समझौता भारतीय सीमाओं के लिए होगा, कृषि निर्यात के लिए होगा, डिजीटल के लिए होगा, हमारी सरकार की सबसे बड़ी चिंता एमएसपी के लिए होगी और पूरी दुनिया में भारत का नया

बाजार खुलेगा। आज केवल यूके के साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, अनेक देश हैं जैसे अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज आदि हैं और जो वोकल फॉर लोकल था, आज हमारी ऊर्जा से जो सम्प्रभुता आई है और हमने टैरिफ के बावजूद भी शेयर बाजार विश्व स्तर पर ले गए हैं। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी प्रधान मंत्री जी के कारण भारत का वोकल फॉर लोकल लोकल टू ग्लोबल बन चुका है।

महोदया, समय की बाध्यता के कारण मैं सभी विभागों की बात नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मैं जानता हूं कि मोदी जी की यह तीसरी सरकार केवल सरकार चलाने के लिए ही नहीं है, यह भारत को विश्व के शिखर पर ले जाने की है। धन्यवाद।